भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या: 2307</u>

<u>बुधवार, 21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र

2307. श्रीमती भावना गवली (पाटील)
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों, विशेषकर नागपुर जिले और रामटेक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) के कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;
(ख) महाराष्ट्र में उन विभिन्न स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की संभावना वाले एनआईएमजेड की स्थापना की जानी है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त की स्थापना के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त की समीक्षा की है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में नए उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ङ) : महाराष्ट्र राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के तहत जुलाई, 2012 में जिला नागपुर, महाराष्ट्र में एनआईएमजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया।

दो निवेश क्षेत्रों अर्थात् औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पास शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी और दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र को मार्च, 2014 में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत एनआईएमजेड के रूप में घोषित किया गया है। इन निवेश क्षेत्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च): सरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ मेक इन इंडिया पहल, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नैशनल सिंगल विंडो प्रणाली, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम, उद्यमी भारत स्कीम, पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान आदि हैं। योजनाओं/पहलों के तहत सहायता महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में उपलब्ध है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 21.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2307 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत निवेश क्षेत्रों का विवरण

1. **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत 18.55 वर्ग किमी क्षेत्र शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), जिला औरंगाबाद:** राज्य सरकार ने शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण 8.39 वर्ग किमी और बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 28.8 वर्ग किमी भूमि एसपीवी को स्थानांतरित कर दी है। मैचिंग इक्विटी की राशि शेंद्रा और बिदकिन के लिए क्रमशः 602.80 करोड़ और 2397.20 करोड़ रुपये भी एसपीवी को जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने 1533.45 करोड़ रुपये के अवसंरचना पैकेजों को अनुमोदित कर दिया है और प्रमुख मुख्य अवसंरचना विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर, 2019 को परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, भारत सरकार 3 क्षेत्रों के विकास के लिए 6414.21 करोड़ रुपये के अवसंरचना पैकेजों को अनुमोदित कर दिया है। सेक्टर-ए (10.32 वर्ग किमी) के लिए प्रमुख मुख्य अवसंरचना कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। एसबीआईए में, 188 भूखंड (544 एकड़) पहले ही औद्योगिक उपयोग और अन्य मिश्रित (वाणिज्यिक और आवासीय) उपयोग के लिए लगभग 6,047 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 9,000 रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता के साथ आबंटित किए जा चुके हैं। एसबीआईए में 962 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए आसानी से उपलब्ध है।

2. **दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत रायगढ़ जिले में 2450 हेक्टेयर का दीघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए):** महाराष्ट्र सरकार ने 6,327 हेक्टेयर भूमि को दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया है, जिसमें से 2,450 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडॉर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) फ्रेमवर्क के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है। परामर्शदाता की नियुक्ति कर परियोजना विकास गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। परियोजना की वित्तीय मॉडलिंग के साथ मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट (पीडीआर) पूरी कर ली गई है। परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

*****